web: www.nyaysakshi.com || पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल || पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरूवार 02 जनवरी 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 95

बिपिन रावत ने संभाला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद

नई दिल्ली (आरएनएस)। पूर्व सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बुधवार को पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका कार्य तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाना है। भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के निर्माण के बारे में कहा कि यह काफी बड़ा और बोल्ड फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सशस्त्र सैनिकों को इससे कैसे मदद मिलेगी।

जनरल बिपिन रावत ने सेना के राजनीतिकरण किए जाने के आरोप कहा कि हम राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। हमें सत्ता में सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करना होता है। जनरल रावत ने यह भी कहा कि तीनों सेनाएं एक टीम के रूप में काम करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जो कार्य दिया गया है, वह तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाना है। हमारी कार्रवाई टीमवर्क पर निर्भर करेगी। हमें अपनी अखंडता और टीम वर्क के माध्यम से बेहतर काम करना होगा।

तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया

इससे पहले उन्होंने नैशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान नए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

2022 तक सीडीएस के पद पर रहेंगे जनरल रावत

बता दें कि जनरल रावत मंगलवार को सेना प्रमुख पद से रिटायर हुए। सोमवार को सरकार ने उन्हें देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया था। वह मार्च 2022 तक इस पद पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन समन्वय के लिए सीडीएस की नियुक्ति हुई है। कारगिल युद्ध के बाद इस पद की मांग उठी थी।

विदाई समारोह में क्या बोले जनरल रावत

अपने विदाई समारोह के दौरान जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना बेहतर तरीके से तैयार है। जनरल रावत ने जटिल परिस्थितियों में अडिग रहने वाले सैनिकों का आभार भी जताया। उन्होंने कहा, श्सेना प्रमुख अकेले कुछ नहीं करता। उसे काम करने के लिए जवानों और सभी रैंक के अधिकारियों से सहयोग की जरूरत होती है।

पीएम मोदी ने रावत को दी बधाई

प्रधानमंत्री ने ट्विट संदेश में कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे ही हम नये वर्ष और नए दशक में प्रवेश कर रहें हैं, भारत को जनरल बिपिन रावत के रूप में अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल रहा है। मैं उन्हें बधाई देता हूं, और इस नयी जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वह एक निष्ठावान अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ देश की सेवा की है। ऐसे समय में जब देश का पहला सीडीएस अपना पदभार संभाल रहा है, वह उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सेवा की है और राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है।

न्याय साक्षी के सभी पाठकों को नव-वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

महत्वपूर्ण एवं खास

इसरो प्रमुख सिवन ने दी गगनयान और चंद्रयान-3 की तैयारियों की जानकारी

बेंगलुरु (आरएनएस)। इसरो प्रमुख के. सिवन ने नए वर्ष पर गगनयान और चंद्रयान-3 मिशन की तैयारियों के बारे में देशवासियों को जानकारी दी। इसरो प्रमुख सिवन ने बताया कि अंतरिक्ष विज्ञान के जरिए हमारा प्रयास देशवासियों के जीवन को और बेहतर बनाने की है। इसरो प्रमुख ने बताया कि दोनों महत्वपूर्ण प्रॉजेक्ट्स के लिए काफी तैयारी बीते हुए साल में ही कर ली गई है। इसरो प्रमुख सिवन ने बताया कि गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्षयात्रियों की पहचान कर ली गई है। 2019 में गगनयान मिशन पर हमने अच्छी प्रगति हासिल की है। इस मिशन के लिए चार अंतरिक्षयात्री चुने गए हैं और जनवरी के तीसरे हफ्ते से उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए नेशनल अडवाइजरी कमिटी बनाई गई है। इसरो चीफ ने बताया कि चंद्रयान-3 प्रॉजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और इस पर काम प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रॉजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। इसका कॉन्फिगरेशन चंद्रयान-2 की तरह ही होगा। इसमें भी लैंडर और रोवर होगा।

यमुना एक्सप्रेसवे पर कार में तीन शव मिलने से मचा हड़कंप

» आत्महत्या की आशंका

मथुरा (आरएनएस)। नए साल के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मथुरा के यमुना एक्सप्रेस-वे पर एक गाड़ी में तीन लोगों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है. मृतक सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं. यमुना एक्सप्रेस-वे पर खड़ी एक हुंडई क्रेटा कार में ये तीनों शव मिले हैं. वहीं गाड़ी में एक बच्चा गंभीर हालत में मिला है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्ट्या कारोबार में घाटा और पारिवारिक कलह के वजह से आत्महत्या जैसा कदम उठाया लग रहा है. पुलिस ने मौके से एक नोट भी बरामद किया है. थाना जमुनापार क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 105 पर बुधवार सुबह एक क्रेटा कार खड़ी मिली. गाड़ी अंदर से लॉक थी. कार न खुलने पर उसका शीशा तोड़ा गया तो अंदर तीन लाशें पड़ी मिली. जबकि एक बच्चे की सांसें चल रही थी. मृतक की पहचान गऊ घाट स्थित लाल दरवाजा निवासी नीरज अग्रवाल, उनकी पत्नी नेहा अग्रवाल और बेटी धान्या अग्रवाल के रूप में हुई है. वहीं बेटे शौर्य अग्रवाल को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया है. मृतक नीरज अग्रवाल सर्राफा व्यवसायी थे.

भारत-पाक ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा की

नई दिल्ली (आरएनएस)। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत और पाकिस्तान ने बुधवार को परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफहमले पर प्रतिबंध के तहत एक-दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान-प्रदान किया है। यह आदान-प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चौनलों के माध्यम से किया गया था। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूची का यह लगातार 20वां आदान-प्रदान है। इस तरह का पहला आदान-प्रदान जनवरी 1992 में हुआ था। बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच यह आदान प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले के निषेध पर हुए समझौते के तहत किया गया। यह समझौता 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित किया गया था और 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों को साल की पहली तारीख यानी एक जनवरी को एक-दूसरे को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी देनी होती है।

केंद्र सरकार की रडार में पीएफआई, यूपी सरकार ने की सिफारिश

» गृह मंत्रालय कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफहुए हिंसक प्रदर्शनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया(पीएफआई) और स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया(एसआईएमआई) के हाथ होने की बात कही है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफइंडिया(पीएफआई) की भूमिका सामने आ रही है। गृह मंत्रालय सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय करेगा। पीएफआई पर स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया(एसआईएमआई) के साथ संबंध होने सहित कई आरोप लगे हैं। इसके साथ ही कई राज्यों ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है।

राज्यों सरकारों के इस बयान पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाने वाले गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संविधान के 245 धारा में लिखा है कि कुछ विषय पर संसद देश के किसी हिस्से या पूरे देश के लिये कानून बना सकता है। आर्टिकल 19 में लिखा है कि नागरिकता को लेकर कानून संसद बना सकता है . संसद द्वारा बनाया कानून पूरे देश मे लागू होगा. संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकता है। गौरतलब है कि यूपी के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने गृह मंत्रालय को चरमपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को प्रतिबंधित करने की सिफारिश करते हुए एक पत्र लिखा है जो गृहमंत्रालय के विचाराधीन है।

तीन तलाक कानून, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि केंद्र की बड़ी उपलब्धि

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार की फौरी तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाना और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि वर्ष 2019 में कानून मंत्रालय की बड़ी उपलब्धियां रहीं हैं।

केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 में संसद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 को अपनी मंजूरी दी। नये कानून ने 'तलाक ए बिद्दत' या तलाक के इस तरह के किसी अन्य प्रारूप को अमान्य एवं अवैध बना दिया। सितंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय में चार नये न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जिससे शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ कर 34 हो गई जो अब तक सर्वाधिक है। हालांकि, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में रिक्तियां बढ़ रही हैं। ऐसे में अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने के वास्ते राज्य सरकारों एवं 25 उच्च न्यायालयों को तैयार करना 2020 में कानून मंत्रालय के एजेंडा में शीर्ष पर होगा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने पर आमराय बनाने के अलावा नये साल में मंत्रालय को उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा।जिला और अधीनस्थ अदालतों में 5,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कानून मंत्रालय ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने की हिमायत की है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि राज्य एवं उच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकते हैं, जबकि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित कर सकती है। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की सेवाएं राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करेगी।

फिलहाल अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार ने निचली न्यायपालिका के लिए एक अलग कैडर गठित करने की दिशा में काफी समय से लंबित प्रस्ताव पर नये सिरे से जोर दिया है। लेकिन अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के अलग-अलग विचार हैं।

दिल्ली में अराजकता बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई, जावडेकर का आप और कांग्रेस पर हमला

नई दिल्ली (आरएनएस)। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोगों को उकसाया, जिसके लिए भाजपा ने इन दलों से जनता के समक्ष माफी मांगने को कहा है।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में दिल्ली में हुई हिंसा के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। जावडेकर ने कहा कि दिल्ली में सीएए के मुद्दे पर हिंसा आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस द्वारा फैलाया गया। आप के विधायक अमंतुल्ला खान ने दंगे भड़काने के लिए बयान दिया जिससे दिल्ली का माहौल खराब हुआ, लेकिन अब दिल्ली और देश की जनता इनकी राजनीति को समझ गई है इसलिए अब दिल्ली में शांति है। सीएए किसी धर्म के खिलाफ नहीं है यह बात सबको समझ आ गई है। आप और कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले दिल्ली का माहौल हम इनको खराब नहीं करने देंगे। उन्होंने सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए बहुत काम किए हैं। हम यह सब काम दिल्ली की जनता तक ले कर जाएंगे और अगले पांच साल में क्या काम करेंगे वो भी जनता तक ले कर जाएंगे।

दिल्ली में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अभी नहीं- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है और जब भी इस पर कोई फैसला होगा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जावड़ेकर विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली भाजपा के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए सकारात्मक तरीके से चुनाव लड़ेगी और जबर्दस्त सफ्लता दर्ज करेगी। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी रणनीति के मुताबिक फैसले लेगी और मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर जब भी कोई फैसला किया जाएगा तो उसकी घोषणा की जाएगी।

आप पर साधा निशाना- केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में फॉगिंग और प्रशिक्षण एमसीडी ने किया जिसका परिणाम हुआ की डेंगू कम हुआ। एमसीडी चुनाव से पहले आप कहती थी की भाजपा को वोट दिया तो डेंगू फैलेगा। अब कम हुआ तो झूठा क्रेडिट लेने आ गई दिल्ली सरकार। अनधिकृत कॉलोनी पर भी झूठा प्रचार कर रही है आ सरकार।

एयर मार्शल एमएसजी मेनन वायु प्रभारी-अधिकारी (प्रशासन) बने

नईदिल्ली (आरएनएस)। एयर मार्शल एमएसजी मेनन वीएसएम ने भारतीय वायु सेना के वायु प्रभारी-अधिकारी प्रशासन के रूप में पदभार संभाल लिया है, जो 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी हो गया है। एयर मार्शल एमएसजी मेनन वीएसएम दिसंबर, 1982 में भारतीय वायु सेना की प्रशासनिक शाखा से जुड़े थे। उन्होंने कालीकट विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।

उन्होंने कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर से उच्च वायु कमान पाठ्यक्रम पूरा किया है। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी हैं। एयर मार्शल एमएसजी मेनन एक कैट 'एवाईई' हवाई यातायात नियंत्रक हैं और उन्होंने एक प्रमुख फ्लाइंग स्टेशन में एक परिचालनरत रडार यूनिट की कमान संभाली है। उन्होंने एक प्रमुख एएफ स्टेशन में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में निदेशक की नियुक्तियों की व्यवस्था की है।

पाकिस्तान की तर्ज पर चीन सीमा पर रहेगी सेना की नजर

» नए आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बोले

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय सेना लंबे समय से पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर निगरानी करती रही है, लेकिन अब चीन सीमा पर भी फोकस किए जाने की जरूरत है।

नए आर्मी चीफ बने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणेने बुधवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को चीन से लगती अपनी सीमा पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सेनाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद उन्होंने कहा कि पिछले दौर में हमने पश्चिमी मोर्चे पर बहुत ध्यान दिया है। अब उत्तरी मोर्चे पर भी उसी तरह से ध्यान दिए जाने की दिए जाने की जरूरत है। देश के लिए किसी भी खतरे से निपटने में सेना सक्षम है। जनरल नरवणेने कहा कि इस दिशा में हम अपनी क्षमता को बढ़ाने में जुटे हैं। हम अपनी उत्तरी सीमा के साथ ही उत्तर पूर्व की सीमा को भी मजबूत करने में जुटे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान

भारत-अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय संस्थागत व्यवस्थाओं जैसे कि संयुक्त आयोग की बैठकों (जेसीएम), संयुक्त व्यापार समितियों (जेटीसी) और संयुक्त कार्य दलों (जेडब्ल्यूजी) के जरिये अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार की नियमित रूप से समीक्षा करता है।

भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति का 9वां सत्र 19-20 अगस्त, 2019 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केन्या में उनके समकक्ष यानी केन्या सरकार के उद्योग, व्यापार एवं सहकारिता मंत्रालय में कैबिनेट सचिव (मंत्री) पीटर मुन्या की सह-अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक के दौरान एमएसएमई, कृषि, सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), पर्यटन, मानकों का संचालन, उच्च शिक्षा में मानव संसाधन का विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, निवेश संवर्धन एवं संरक्षण, हवाई सेवाएं, ऊर्जा, प्लास्टिक, दवाओं, तेल एवं गैस, स्वास्थ्य, आव्रजन या अप्रवास, ऑटोमोबाइल एवं अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे कई विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। केन्या में भारतीय औषधकोश (फार्माकोपोइया) को मान्यता देने के मुद्दे के क्षेत्र में सहयोग करने पर भी चर्चाएं की गईं।

व्यापार एवं निवेश पर गठित भारत-दक्षिण अफ्रीका जेडब्ल्यूजी की पहली बैठक जनवरी, 2019 में आयोजित की गई थी, ताकि गैर-शुल्क बाधाओं सहित अन्य अवरोधों पर विचार-विमर्श किया जा सके तथा इस क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए आगे की राह के बारे में सुझाव दिये जा सकें।